



## सेंसेक्स में 76 अंकों की उछाल

वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच शेयर बाजार सेंसेक्स 76 अंक की बढ़त के साथ 80,787.30 अंक पर बंद हुआ। } 14

## चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को वैश्विक व्यापार चुनौतियों को नए अवसरों में बदलने के लिए अपनी असाधारण क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए। } 16

## आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दस्तावेज के रूप में शामिल करने का दिया निर्देश

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करे।

फिलहाल, बिहार में एसआईआर के लिए 11 निर्धारित दस्तावेज हैं जिन्हें मतदाताओं को अपने प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा। हालांकि, न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए मतदाता द्वारा



को ही मतदान करने की अनुमति हो और जाली दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक होने का दावा करने वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए। पीठ ने निर्वाचन आयोग को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मतदाताओं से आधार कार्ड स्वीकार नहीं करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को जारी कि, गए कारण बताओ नोटिस पर भी आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। आयोग की ओर से विरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6 प्रतिशत ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार को ...शेष पृष्ठ 14 पर

## सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए भेजी राहत सामग्री

समय पर किये गये प्रावधानों के चलते बाढ़ आपदा से बचा है यूपी विशेष/जिला संवाददाता



लखनऊ/सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित नागरिकों के लिए राहत सामग्री से लदे 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरोवर पोर्टिको, अंबाला रोड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि राहत सामग्री मानवीय संवेदना की महत्वपूर्ण कड़ी है। संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इन तीनों राज्यों के अपने बहन-भाइयों के साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम योगी ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज

उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन का जिम्मा जवाब देते हुए कहा कि विकास के नित नए प्रतिमान

एक परिवार के लोग पैसा लेकर करते थे भर्ती : सीएम विशेष संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2016 समेत पहले की भर्ती प्रक्रियाओं पर निशाना साधा। कहा कि हमें कई भर्तियों को सीबीआई को देना पड़ा था। एक व्यक्ति आठ-आठ जगह नाम लिखाकर पैसा लिए जा रहा था, जब जांच हुई तब पता चला। यह एक परिवार के वही लोग हैं, जो पैसा लेकर भर्ती करते थे और यूपी की जनता को लूटते थे। अभी भी जांच चल रही है। समय पर जांच हो जाएगी तो महाभारत के बहुत रिश्ते बाकी का जीवन जेल में बिताने को मजबूर होंगे। उनके कारनामों यूपी को विकास की बुलंदियों को हटाने की बजाय गत की ओर धकेल रहे थे। इन लोगों ने यूपी को बीमार बना दिया। इससे पहचान का संकट हो गया। नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी ...शेष पृष्ठ 14 पर

## संक्षेप मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, दो जवान शहीद

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को मुठभेड़ में दो आतंकीवादी मारे गए और दो सैनिक शहीद हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने गुडार वन क्षेत्र में आतंकीवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकीवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलाबारी चलाए जाने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कुलगाम के गुडार जंगल में संयुक्त तलाश अभियान चलाया। पोस्ट में कहा गया कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और आतंकीवादियों को ललकारा, जिसपर आतंकीवादियों ने गोलेबारी शुरू कर दी।

## 28 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला

लखनऊ। यूपी में सोमवार की शाम बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिये गये। इनमें कई डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारी हैं। कुल 28 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। मुरादाबाद में ही डॉ भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सभरवाल को पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आईजीआरएस, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ए सतीश गणेश को लंबे समय बाद देबारा लखनऊ लाया गया है। वह अभी तक पीटीसीएस मुगदाबाद में अपर ...शेष पृष्ठ 14 पर

# नेपाल में हिंसा, 22 मरे, गृहमंत्री का इस्तीफा

काठमांडू समेत कई शहरों में तोड़फोड़ व आगजनी एहतियात के तौर पर लगाया कर्फ्यू भारत के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी चौकसी



एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य इलाकों में सोमवार को युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके दौरान कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने काठमांडू और देश के अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं भारत में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, जहां सशस्त्र सीमा बल (एसएफबी) और स्थानीय पुलिस सुरक्षा निगरानी करती हैं। इनमें कई जिलों के नागरिकों ने बताया कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने से दोनों तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलामपुर जिले में नेपाल में जारी आंदोलन को देखते हुए सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उधर से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। काठमांडू में हालात को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को सेना को तैनात करना पड़ा। काठमांडू में जेन जी के बैनर तले स्कूली छात्रों समेत हजारों युवा

## 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के बाद फैली हिंसा

नेपाल में सोशल मीडिया की दीवानी किस कदर लोगों के दिलों-दिमाग पर सवार हो गई है, इसका जीता जागता उदाहरण इन दिनों नेपाल में देखा जा सकता है। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के केपी शर्मा ओली सरकार के कदम का देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग इस बैन वाले फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, इस प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक घायल हैं। नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन से स्पष्ट होता है कि आज का युवा सोशल मीडिया का बस शौकीन ही नहीं, लगभग उसका बंदी बनता जा रहा है। रिलस की लत, वायरल ट्रेंड्स की दीवानी और खुद को फेमस करने की चाहत ने एक ऐसी दुनिया रच दी है, जहां असली जीवन कहीं पीछे छूटता जा रहा है और सोशल मीडिया से दूर होने का डर घातक प्रदर्शन का रूप लेता जा रहा है।

ज्यादा गिरफ्त में माना जा रहा है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया कई देशों में हुई क्रांति का जरिया बना था, अब नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर ही क्रांति हो रही है। असल में नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह 3 सितंबर को सोशल मीडिया की 26 साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, जिनमें युवाओं में बेहद प्रचलित फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल हैं। दरअसल, नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्पष्ट कहना था कि इन प्लेटफॉर्मों ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सभी को 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। जैसे ही सोशल साइट्स पर बैन लगा, जेनरेशन ...शेष पृष्ठ 14 पर

और एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल में है। न्युज पोर्टल खबरबन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि जेन जी आंदोलन में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दो सुरक्षाकर्मियों समेत 42 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज वर्तमान में काठमांडू के सिविल अस्पताल में चल रहा है। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने राजधानी के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। यह विरोध प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल गया है। काठमांडू जिला प्रशासन ने संसद भवन के आसपास के क्षेत्रों में अशांति को रोकने के लिए अपराह्न 12:30 बजे से रात 10:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की। मुख्य जिला अधिकारी छवि लाल रिजाल ने एक नोटिस में कहा, प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों के आवागमन, प्रदर्शन, बैठक, सभा या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन ने बाद में ये प्रतिबंधात्मक आदेश राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू कर दिए। नेपाल सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर चार सितंबर को फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध उन्हें विनियमित करने के लिए लगाया गया है, लेकिन आम जनता ...शेष पृष्ठ 14 पर

विशेष खबर राज्यसभा के 233 व लोकसभा के 543 सदस्य करेंगे मतदान

## अगला उप राष्ट्रपति कौन, सांसद आज करेंगे फैसला

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को तय करेंगे कि सी. पी. राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी में से देश का अगला उप राष्ट्रपति कौन होगा। राधाकृष्णन, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा। मंगलवार देर शाम तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पी.



सी. पी. राधाकृष्णन बी. सुदर्शन रेड्डी

सी. मोदी ने कहा है कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101, वसुधा में होगा। देश के 17वें उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं), तथा 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। संसद के हालिया

मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उनका कार्यकाल दो साल बचा हुआ था। इनके इस्तीफे के कारण यह चुनाव हो रहा है। विभिन्न दलों द्वारा दिए गए समर्थन को आधार बनाकर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजग उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी बार-बार यह कहकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई वैचारिक है तथा यह मतदान सिर्फ उप राष्ट्रपति चुनने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की भावना के लिए है। चुनाव से एक दिन पहले, विपक्ष के सांसदों ने एक जुटकर प्रकट करते हुए बैठक की और मांक ...शेष पृष्ठ 14 पर

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार गैरकानूनी कृत्यों पर कठोरता से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर कोई रियायत न बरते, सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्देश सीएम कैम्प कार्यालय में आयोजित शासन पुलिस के विरिष्ठ अधिकारियों को दिए। बैठक में सभी जिलों के डीएम व एसपी वरचू अली जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि अनधिकृत आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन जारी करने वालों पर नियमित कार्रवाई की जाए। बाहरी व्यक्तियों व सदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग और सख्ती बढ़ाई जाए तथा सदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। गौवंश के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था,

# आमजन से व्यवहार ठीक रखें जनसेवक, दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं: योगी

## प्रदेश भर से आये पीड़ितों की समस्याओं से मुखातिब हुए सीएम योगी, निस्तारण के दिए निर्देश, जमीन से जुड़े मामले लेकर भी पहुंचे फरियादी

### विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आये पीड़ितों की शिकायतें सुनीं

- सहारनपुर से आई महिला ने राशन कार्ड न होने पर राशन डीलर द्वारा अभद्रता की शिकायत की
- सीआरपीएफ के जवान की भी सुनी समस्या, मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन से कहा- शीघ्र निराकरण कराएं
- मुख्यमंत्री ने गाजीपुर से आये दिव्यांग की सुनी फरियाद, इलेक्ट्रॉनिक वॉकिंग स्टिक भेंट की
- आर्थिक सहायता का पत्र लेते हुए सीएम ने महिला से कहा- हॉस्पिटल से लेकर एस्ट्रिमेंट दें, सरकार सहायता करेगी

और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। सहारनपुर से आई महिला ने बताया कि उनके पास राशन



कार्ड नहीं है। जब वे राशन लेने गईं तो राशन डीलर अभद्रता करता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जनसेवक आमजन से व्यवहार ठीक रखें। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा।

**जमीन के आए मामलों का भी लिया संज्ञान** : सोमवार को 'जनता

दर्शन' में सर्वाधिक मामले जमीनी विवाद से जुड़े आए। प्रयागराज से आए सीआरपीएफ के जवान ने भी जमीन से जुड़े मामले को लेकर सीएम आदित्यनाथ ने पत्र लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया।

'जनता दर्शन' में आई मंजू देवी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि अपोलो में इलाज चल

करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों का भविष्य किसी भी हाल में दांव पर नहीं लगाया जाएगा।

15 दिन में शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट : जांच प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर जांच पूरी कर 15 दिनों के भीतर शासन को समेकित रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह कार्यवाही सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जांच की पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

- हर मंडल में होगा विशेष जांच टीम का गठन, शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच करेगी टीम
- 15 दिन में शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट, अनियमितता पर होगी कठोर कार्रवाई
- शैक्षणिक संस्थानों की जांच की पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त रखेंगे प्रत्यक्ष निगरानी
- सीएम योगी की अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

ऐसे संस्थानों को छात्रों से लिया गया संपूर्ण शुल्क ब्याज सहित वापस

करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों का भविष्य किसी भी हाल में दांव पर नहीं लगाया जाएगा।

15 दिन में शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट : जांच प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रत्येक जनपद स्तर पर जांच पूरी कर 15 दिनों के भीतर शासन को समेकित रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह कार्यवाही सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जांच की पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रहा है। इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिला दी जाए। इस पर सीएम ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद मरीज को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। आप भी अस्पताल से एस्ट्रिमेंट बनवाकर भिजवाएं। आपके इलाज में खर्च की चिंता सरकार करेगी। 'जनता दर्शन' में दिव्यांग भी पहुंचे। गाजीपुर से दिव्यांग उधम यादव ने पेंशन बढ़ाने, आयुष्मान कार्ड, हैंडपंप व आवास दिलाने को लेकर सीएम को प्रार्थना पत्र दिया। सीएम ने तत्काल उनकी समस्या के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अफसरों को निर्देश दिया। सीएम ने उधम यादव को इलेक्ट्रॉनिक वॉकिंग स्टिक भी प्रदान की।

**बच्चों को दी चॉकलेट, पढ़ाई के बारे में पूछा** : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में अभिभावकों के साथ आए बच्चों को दुलारा-युचकारा। नहे-मुन्नों के सिर पर हाथ फेर अपनत्व का अहसास कराया। कुछ बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। सीएम योगी ने चॉकलेट-टॉफी प्रदान किया और पढ़-लिखकर बच्चों को उज्वल भविष्य बनाने का आशीर्वाद दिया।

## युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना कौशल विकास मिशन की प्राथमिकता

लखनऊ। लखनऊ स्थित कौशल विकास मिशन मुख्यालय में सोमवार को प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु आयोजित छठवें दिवस की ओरिएंटेशन कार्यशाला की अध्यक्षता अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षण प्रदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद कर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। महिला एवं युवा सशक्तिकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए मिशन मोड में कार्य हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को उपयुक्त एवं टिकाऊ प्लेसमेंट दिलाना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने उद्यमिता विकास पर बल देते हुए कहा कि उद्योगोन्मुख कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को उद्योगों में सीधे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

## नवचयनितों ने निष्पक्ष ढंग से मिली नियुक्ति के अनुभव किए साझा

### विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत उग्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में चयनित 1,112 कनिष्ठ सहायकों एवं 22 एकसरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिया गया। इनमें से कोई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में नियुक्ति पत्र दिया। नवचयनितों ने एक सुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से हम युवाओं को कड़ी मेहनत का फल प्राप्त हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए उनका आभार जताया। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष व शुचितापूर्ण हुई भर्ती प्रक्रिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें बिना भेदभाव, बिना कोई पैसे दिए और बिना किसी सिफारिश के सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है।

**भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी नीति**

**से युवाओं को मिल रही स्वास्थ्य नौकरी** : पंखुडी : उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुई सीतापुर की पंखुडी गुप्ता मानती हैं कि ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। आज युवा कड़ी मेहनत के दम पर पारदर्शी तरीके से चयनित होकर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। इस वजह से मुझे भी सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद देती हूँ।

**युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के प्रति संकल्पित है मुख्यमंत्री** : वैभव : कनिष्ठ सहायक सीतापुर के वैभव मिश्रा ने अपने भाव साझा करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है। आज का कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योगी सरकार तेज रफ्तार से युवाओं को नियुक्ति दे रही है। मुख्यमंत्री जी युवाओं के उज्वल भविष्य के प्रति कृत संकल्पित हैं। रिक्त युवाओं की निष्पक्ष नियुक्तियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।

**अब सिर्फ काबिलियत के दम**

**पर मिलती है नियुक्ति** : श्रद्धा शुक्ला : श्रद्धा शुक्ला ने कहा कि पहले की सरकारों में नियुक्ति के लिए रिश्तत देनी पड़ती थी, लेकिन आज नियुक्ति सिर्फ काबिलियत के दम पर मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए रिश्तत गुज्र जमाने की बात हो गई। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति देकर उत्तम प्रदेश का नया मार्ग बनाया है। इस नौकरी के लिए सिफारिश या एक रुपये रिश्तत भी नहीं देनी पड़ी। इसके लिए मुख्यमंत्री का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।

**योगी सरकार नौकरी देने से लेकर सुरक्षा देने में है संवेदनशील** : आदित्य पाठक : अयोध्या के आदित्य पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री की वजह से हम सभी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन पा रहे हैं। सरकार सुरक्षा से लेकर रोजगार देने तक संवेदनशील है। आठ वर्ष में महिलाओं को भी बड़ी तादाद में नियुक्तियां दी गई हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में महिलाएं खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रही हैं। योगी हमारे लिए नंबर 1 हैं।

## विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होगी सघन जांच

### उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी ने दिये आदेश

### विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

**हर मंडल में विशेष जांच टीम का होगा गठन** : मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब प्रत्येक मण्डलायुक्त अपने-अपने मण्डल के तहत आने वाले सभी जनपदों में विशेष जांच टीम गठित करेंगे। इन टीमों में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस विभाग का अधिकारी और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी अनिवार्य रूप से

शामिल होगा। यह टीम जमीनी स्तर पर जांच कर संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की हकीकत सामने लाएगी।

**शैक्षणिक संस्थाओं के शपथपत्र और मान्यता-पत्र होंगे अनिवार्य** : जांच के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक संस्था से शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि संस्थान केवल उन्हीं कोर्सों का संचालन कर रहा है, जिन्हें नियामक निकाय, विश्वविद्यालय या बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही, संचालित सभी कोर्स की सूची और उनके मान्यता-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र का दाखिला बिना मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए।

**अनियमितता पर होगी कठोर कार्रवाई** : अगर जांच में किसी संस्थान में अवैध प्रवेश या बिना

मान्यता के कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं,

- हर मंडल में होगा विशेष जांच टीम का गठन, शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच करेगी टीम
- 15 दिन में शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट, अनियमितता पर होगी कठोर कार्रवाई
- शैक्षणिक संस्थानों की जांच की पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त रखेंगे प्रत्यक्ष निगरानी
- सीएम योगी की अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

ऐसे संस्थानों को छात्रों से लिया गया संपूर्ण शुल्क ब्याज सहित वापस

## सरकार की अनदेखी से बाढ़ पीड़ित परेशान

**लखनऊ।** सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश में बाढ़ से स्थिति भयावह है। दर्जनों जिलों के सैकड़ों गांव और कई नगरीय क्षेत्र बाढ़ से घिरे हैं। लाखों की आबादी और पशु संकट में है। मथुरा से लेकर आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, सीतापुर, हरदोई, वाराणसी से लेकर कई जिलों में बाढ़ से स्थिति खराब है। बाढ़ से आम जनजीवन संकट में है। लोगों को खाना-पानी, दवा-इलाज नहीं मिल रहा है। इस संकट की घड़ी में सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के घर-खेतीबाड़ी सब बर्बाद हो गये। बाढ़ राहत को लेकर बनी मुख्यमंत्री की टीम इलेवन का गुच्छ पता नहीं है। जनता को सरकार की थोथी घोषणाओं से कोई राहत नहीं मिल रही है। लोगों को जान बचाने के लाले पड़े है।

## नियामक आयोग ने बिजली की नयी दरें जारी कीं, ट्रांसमिशन टैरिफ में बदलाव

### वरिष्ठ संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के भीतर बिजली के ट्रांसमिशन टैरिफ को निर्धारित कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब प्रति यूनिट ऊर्जा ट्रांसमिशन के बजाय क्षमता के आधार पर टैरिफ तय किया जाएगा। आयोग ने टैरिफ निर्धारण की पद्धति में यह महत्वपूर्ण बदलाव के मल्टी इयर टैरिफ फॉर ट्रांसमिशन विनियम, 2025 के अनुरूप किया है। इस नए प्लान में सभी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों की लागत को एक साथ जोड़कर सभी वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य ट्रांसमिशन सेवा उपयोगकर्ताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। राज्य के डिस्कॉम और भारतीय रेल से

2,13,284.55 रुपए प्रति टहट प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाएगा। वहीं, अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को 0.2674 रुपए प्रति की दर से भुगतान करना होगा। इससे राज्य-स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर बोझ कम होगा। अंततः इसका लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्हें वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही यह नई व्यवस्था राज्य भर में ओपन एक्सेस और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 और डाटा सेंटर नीति, 2021 के तहत निर्धारित छूट भी लागू होगी। आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या आम लोगों को राहत मिलेगी या परेशानी बढ़ेगी, इसकी बात की जाए तो नई व्यवस्था राज्य-स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारियों पर बोझ कम करेगी।

## भवन की डिजाइन उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुरूप करने : आनंदीबेन

### विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** राजभवन में लोक निर्माण विभाग तथा विद्युत विभाग द्वारा निर्मित सात निर्माण कार्यों का उद्घाटन सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन के गांधी सभागार में किया। इनमें पुराने कोयला गोदाम का जीर्णोद्धार कर ओपन मोटर गैराज का निर्माण, पुराने डीजी सेट के स्थान पर

- राजभवन में लोक निर्माण विभाग तथा विद्युत विभाग द्वारा निर्मित विविध निर्माण कार्यों का राज्यपाल ने किया उद्घाटन

अत्याधुनिक 400 केवीए क्षमता के दो नए जनरेटर की स्थापना, ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से 400 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना, राजभवन परिसर में अग्निशमन प्रणाली का उच्चीकरण, गांधी सभागार में आधुनिक विलर टाइप वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना, मुख्य भवन के



पुराने किचन को नवीनतम तकनीक से सुसज्जित कर्मशियल किचन में परिवर्तित करना तथा मुख्य भवन, सचिवालय और कर्मयोगी भवन की छतों पर चाइना मोड्यूल कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से राजभवन परिसर न केवल और अधिक सुंदर एवं सुसज्जित हुआ है, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी सुदृढ़ एवं पर्यावरण अनुकूल बन गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी

को बधाई देते हुए कहा कि बहुत ही सुंदर निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन की नींव (फाउंडेशन) मजबूत होने पर ही वह लंबे समय तक टिकाऊ बनता है। इसलिए निर्माण कार्यों में उत्तम गुणवत्ता के पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग ने समय और लागत का ध्यान रखते हुए

टिकाऊ निर्माण कार्य किए हैं, यह अनुकरणीय है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और वह सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो उससे संतोष की अनुभूति होती है। कार्यक्रम में मौजूद इंजीनियरों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसी भी भवन के निर्माण से पूर्व उसकी डिजाइन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भवन की उपयोगिता के अनुसार ही उसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि आंगनबाड़ी के लिए भवन बनाया जा रहा है तो उसकी डिजाइन छोटे बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि उस भवन का वास्तविक लाभ मिल सके। नवयुगीन आवश्यकताओं के अनुसार ही भवनों के डिजाइन बनाए जाने चाहिए। डिजाइन बनाने समय दीर्घकालिक उपयोग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही बचत पर जोर देना चाहिए और फिजूलखर्ची से बचना चाहिए। राज्यपाल ने खुले और हवा में

लटकते विद्युत तारों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हें अब अंडरग्राउंड करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित उपयोग हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि राजभवन में हुए सभी निर्माण कार्यों के डिजाइन सुरक्षित रखे जाएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विस्तार या नए कार्य की आवश्यकता होने पर समय की बचत हो और कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके। अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डॉ सुधीर महादेव बोबडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डॉ. पंकज एल जानी, ओएसडी राज्यपाल अशोक देसाई, विशेष सचिव राज्यपाल श्रीप्रकाश गुप्ता, लोक निर्माण एवं विद्युत विभाग के अधिकारी, राजभवन के अधिकारी-कर्मचारी सहित अन्य महानुभाव उपस्थित रहे।

## छह जिलों में तैनात किये गये नये सीएमओ

**लखनऊ।** मथुरा, हरदोई, आजमगढ़ सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में नये मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) की तैनाती की गई है। प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारियों को इन जिलों में सीएमओ बनाए जाने का आदेश सोमवार को शासन की विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने जारी कर दिया। सुल्तानपुर के एसीएमओ डा. राधा वल्लभ को मथुरा, संतकबीर नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डा. भवनाथ पांडेय को हरदोई का सीएमओ बनाया गया है। बागपत की एसीएमओ डा. दीपा सिंह रामपुर, महाराजगंज के एसीएमओ डा. राजेंद्र प्रसाद एटा के नये सीएमओ होंगे। जालौन के जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. ननक राम को आजमगढ़ में और आगरा के जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डा. चंद्रप्रकाश को कुशीनगर में सीएमओ पद पर तैनाती दी गई है। इन सभी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

## आराधना मिश्रा मोना ने लड़कियों के अपहरण पर एसआईटी बनाने की मांग की

**लखनऊ।** वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में कांग्रेस की दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लड़कियों के हो रहे अपहरण पर चिंता जताई है और एसआईटी गठित करने की मांग की है। आराधना मिश्रा मोना ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अंबेडकर नगर में बेहद चिंता के वाला प्रकरण सामने आया है, जहां पिछले एक माह में अंबेडकर नगर के 18 थानों में 56 लड़कियों के अपहरण की प्राथमिक दर्ज की गई है, यह सामान्य घटना नहीं है, यह सुनिश्चित बहुत बड़ी साजिश प्रतीत होती है। यह प्रकरण बहुत ही गंभीर है। इसकी घटना की उच्चस्तरीय एसआईटी गठित कर जांच कराई जाए, ताकि जांच होकर सच्चाई पता चल सके और अपराधियों पर कार्रवाई हो सके।

- नेता विधानमंडल दल ने सीएम योगी को लिखा पत्र



























